Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2581- 6306

ग्रामीण विकास स्तर एवं संधृत नियोजनः जनपद फतेहपुर, उ0 प्र0 का एक प्रतीक अध्ययन

आर0 एस0 चन्देल
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग,
कमला नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय तेजगाँव, रायबरेली, उ0 प्र0

शोधसार - ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करने से है। लेकिन वर्तमान भारत में ग्रामीण विकास एक मूलभूत एवं जटिल समस्या के साथ प्रमुख उद्देश्य एवं नियोजनात्मक प्रक्रिया भी है, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या के जीवन को प्रमुखता प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रियान्तर्गत ग्रामीण पर्यावरण, ग्रामीण जनसंकुल विशेषतः गरीब एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों को लक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भूगोलविदों, समाज वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, नीतिनियोजकों, प्रशासकों और राजनीतिज्ञों द्वारा ग्रामीण समाज की संरचना, सामाजार्थिक साधनों का भू–वैन्यासिक विस्तार, नेतृत्व स्वरुप तथा जनसहभागिता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए ग्रामीण समाज के सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं सीमित साधनों के मद्देनजर सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास की कल्पना समुचित ग्रामीण विकास के अभाव में साकार नही हो सकती। भारत गाँवों का देश है यदि गाँव सम्पन्न होंगे तो देश सम्पन्न होगा, यदि गाँव विपन्न होंगें तो देश विपन्न होगा। ग्रामीण विकास के महत्व को स्पष्ट करते हुए *महात्मा गांधी* ने कहा था कि 'प्रत्येक ऑख से ऑसू पोछना हमारा ध्येय होना चाहिए।' यही मूल कारण है कि हमारी विकास नीतियों, योजनाओं और राष्ट्रीय उन्नयन के विविध कार्यक्रमों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्व सर्वोपरि रहा है। सम्प्रति आज राष्ट्र के विकास एवं उत्थान में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एवं उत्थान, मूल मन्त्र सिद्ध हो रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 'जनपद फतेहपुर, उ0 प्र0 में ग्रामीण विकास' स्तर का मापन कर संधृत सुझाव प्रस्तुत करना है। ग्रामीण विकास स्तर के मापन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण विकास अपेक्षित स्तर का नही है बल्कि असन्तुलित है परन्तु ग्रामीण विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं निहित है। इसलिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण विकास के प्रमुख घटकों विशेषतः कृषिगत विविधता हेतु कृषि भूमि के बेहतर उपयोग के लिए बाजार मांग तथा कृषि पारिस्थितिकीय को ध्यान में रखते संधृत नियोजन आवश्यक ही नही बल्कि अपरिहार्य भी है।

शीर्ष शब्द - ग्रामीण विकास, कृषि विशिष्टीकरण, कृषिगत विविधता, जीविकोपार्जित कृषि, कृषि अनुषंगीय व्यवसाय, अवस्थापनात्मक तत्व, विकेन्द्रीकरण, संधृत, यादृच्छिक, 'वर्गीकरण विधि', दोआब, अवनलिकाए।

प्रस्तावना - भारत एक ग्राम्य प्रधान देश है, जहाँ परम्परायें, सामाजिक रीति–रिवाज, धर्म, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण आदि उसकी पहचान है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र उक्त कारणों से आर्थिक एवं सामाजिक रुप से पिछड़ा रहा है, हम अपने इस ग्रामीण सामाजार्थिक विपन्नता के प्रति न्यूनाधिक मात्रा में सदैव से जागरुक रहे हैं, किन्तु ग्रामीण विकास की सारी योजनायें अपने उद्देश्य को पाने में असफल रही हैं। इस बारे में *मेहता कमेटी* (1984) की रिपोर्ट तथा *दर्शन कर चौधरी* आदि के वैयक्तिक अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि विकास योजनाओं का लाभ बहुसंख्य निम्न वर्गीय कृषक एवं कृषक मजदूरों को नही मिल पा रहा है, मिला भी है तो केवल उच्च एवं मध्यम वर्ग के बड़े कृषकों को। यहाँ तक है कि गाँव की कृषि–अर्थव्यवस्था सबको संतुलित एवं समुचित भोजन, रोजगार एवं आवास की सुविधा देने लायक नही रह गयी है। कृषकों को उनकी लागत मूल्य तक नही मिल पा रहा है। कृषकों को आज भी कभी सूखा तो कभी बाढ़ के दुश्चक्र से जूझना पड़ रहा है। कृषकों की खेती आज भी मानसून पर निर्भर है, जबकि कृषि ग्रामीण जीवन की आधार शिला है, जो ग्रामीण जीवन के आर्थिक एवं सामाजिक पक्षों को सुदृढ़ करती है तथा बहुत सीमा तक ग्रामीण विकास के स्वरुप एवं प्रकार को प्रभावित एव निर्धारित करती है।

भारत में धरातलीय विविधता, मृदा विविधता, मौसमी अनिश्चितता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, खेतिहर भूमि की उपलब्धि, समीपता एवं बिखराव, पांरम्परिक जीविकोपार्जित कृषि व्यवस्था आदि के कारण कृषि में विविधता प्रारम्भ से ही रही है। जहाँ धरातल एवं वर्षा अधिक विचलनशील हो, सिंचाई के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध न हो, वहाँ कृषक एक से अधिक फसलों को उपजानें एवं अन्य कृषि अनुषंगीय व्यवसायों को अपनानें में विश्वास करतें हैं, क्योंकि कृषि विविधता कुछ सीमा तक कृषि उपज बीमा सादृश्य होती है, साथ ही मृदा उर्वरता बनाये रखनें, रोजगार की दृष्टि से कृषक वर्ष भर फसलों को बोने, काटनें, मण्डी तक ले जाने आदि क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। कृषि विविधता की मात्रा ग्रामीण विकास के स्तर पर भी निर्भर करता है। जहाँ एक तरफ उच्च विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करनें वाले धनी कृषक कृषि विशिष्टीकरण की तरफ अग्रसर होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व जीविकोपार्जित कृषक कृषि विविधता में विश्वास करते हैं। कृषिगत विविधता में स्थानिक एवं मौसमी अन्तर भी देखा जाता है (चन्देल*, आर0 एस0 एवं सिंह, संजय कुमार,*, 2011)।

ग्रामीण लोगों का मुख्य आर्थिक आधार कृषि एवं विविध कृषि अनुषंगीय व्यवसाय होता है। इसलिए संधृत ग्रामीण विकास हेतु कृषिगत विविधता नियोजन एक महत्वपूर्ण पक्ष है। वस्तुतः ग्रामीण विकास को किसी एक अवखण्ड के विकास के रुप में नही देखा जाना चाहिए, बल्कि समग्रता को ध्यान में रखना चाहिए। इसे स्पष्ट करते हुए *हैरिस* (1982) महोदय ने लिखा है कि "ग्रामीण विकास को नीति और प्रक्रिया उपागम के रुप में देखना चाहिए जो सम्पूर्ण आर्थिक तंत्र विकास को आत्मसात करता है।" कुछ लोगों ने ग्रामीण विकास को गरीबी और असमानता दूर करने के सिद्धान्त को दर्शाया है। जबकि *टेलर* (1975) महोदय ने ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया के रुप में परिभाषित किया है, जिसका उद्देश्य नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के मध्य होने वाले अग्रगामी एवं पश्चगामी अर्न्तसम्बन्ध के माध्यम से करना

है। इस सब की प्रतिपूर्ति संधृत कृषि विकास से ही सम्भव हो सकता है, क्योंकि इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ता है। किसानों के सामाजार्थिक स्तर में सुधार होता है तथा क्षेत्र का आर्थिक तन्त्र सुदृढ़ होता है।

अध्ययन का उद्देश्य एवं विधितन्त्र

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 'जनपद फतेहपुर, उ0 प्र0 में ग्रामीण विकास' स्तर का मापन कर संधृत सुझाव प्रस्तुत करना है। वास्तव में किसी भी क्षेत्र के ग्रामीण विकास का स्तर वहाँ पाये जाने वाले कृषिगत विविधता एवं गहनता पर निर्भर करता है। इसकी प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग एवं अवस्थापनात्मक तत्वों का नवसृजन व विकेन्द्रीकरण तथा कृषि विकास प्रक्रियाओं का समुचित संचालन एवं अंगीकरण आवश्यक है। शोध विषय वस्तु से सम्बन्धित चयनित अध्ययन क्षेत्र जनपद फतेहपुर का विकासखण्ड स्तरीय अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। ग्रामीण विकास' से सम्बन्धित विविध तथ्यों का न सिर्फ स्थानिक अपितु कालिक वितरण प्रारुप को विश्लेषित करने के लिए विगत साढ़े तीन दशकों (1990–91 एवं 2015–16) के आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण विकासखण्ड स्तर पर किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों एवं सूचनाओं का संग्रह यादृच्छिक आधार पर प्रतिचयनित किये गये ग्रामों के कृषकों से व्यक्तिगत सम्पर्क, निरीक्षण, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली द्वारा किया गया है। ग्रामीण विकास स्तर का मापन एवं विश्लेषण विभिन्न सामाजार्थिक घटकों द्वारा 'वर्गीकरण विधि' (Taxonomic Method) के माध्यम से किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का चयन एवं परिचय

किसी सर्वमान्य समस्या से निजात पाने के लिए अध्ययन क्षेत्र का चुनाव भौगोलिक अध्ययन का प्रथम पायदान होता है। इसी सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए अध्ययन हेतु जनपद फतेहपुर, उ0 प्र0 को प्रचयनित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र (जनपद फतेहपुर) गंगा–यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित एवं विस्तृत है, जिसकी स्थिति एवं विस्तार 25° 26′ से 26° 14′ उत्तरी अक्षांश तथा 18° 13′ से 81° 21′ पूर्वी देशान्तर के मध्य (मानचित्र –1) है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत 3 तहसीलें यथा खागा, बिन्दकी एवं फतेहपुर, 13 विकासखण्ड (असोथर, तेलियानी , बहुवा, भिटौरा, हसवा, अमौली, खजुहा, देवमई, मलवां, धाता, ऐराय, विजयीपुर तथा हथगांम), 1516 राजस्व गाँव, 132 न्याय पंचायतें, 789 ग्राम पंचायतें, 2 नगर पालिका (फतेहपुर एवं बिन्दकी) तथा 4 नगर पंचायतें (खागा, बहुवा, किशुनपुर एवं जहानाबाद) समाहित है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 4843.75 वर्ग किमी. है, जिसमें 2632733 (2011) लोग निवास करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र गंगा–यमुना के दोआब में स्थित है, जिसका अधिकांश धरातलीय भाग समतल है जबकि नदियों के किनारे धरातल ऊबड़–खाबड़ तथा रेतीली व कंकरीली है। जनपद में अनेकों नदियां, नाले एवं अवनलिकाएं प्रवाहित होकर गंगा व यमुना नदी में विलीन हो जाती है। जनपद का उत्तरी सम्भाग का जल गंगा तथा दक्षिणी सम्भाग का जल यमुना में विलीन हो जाता है।

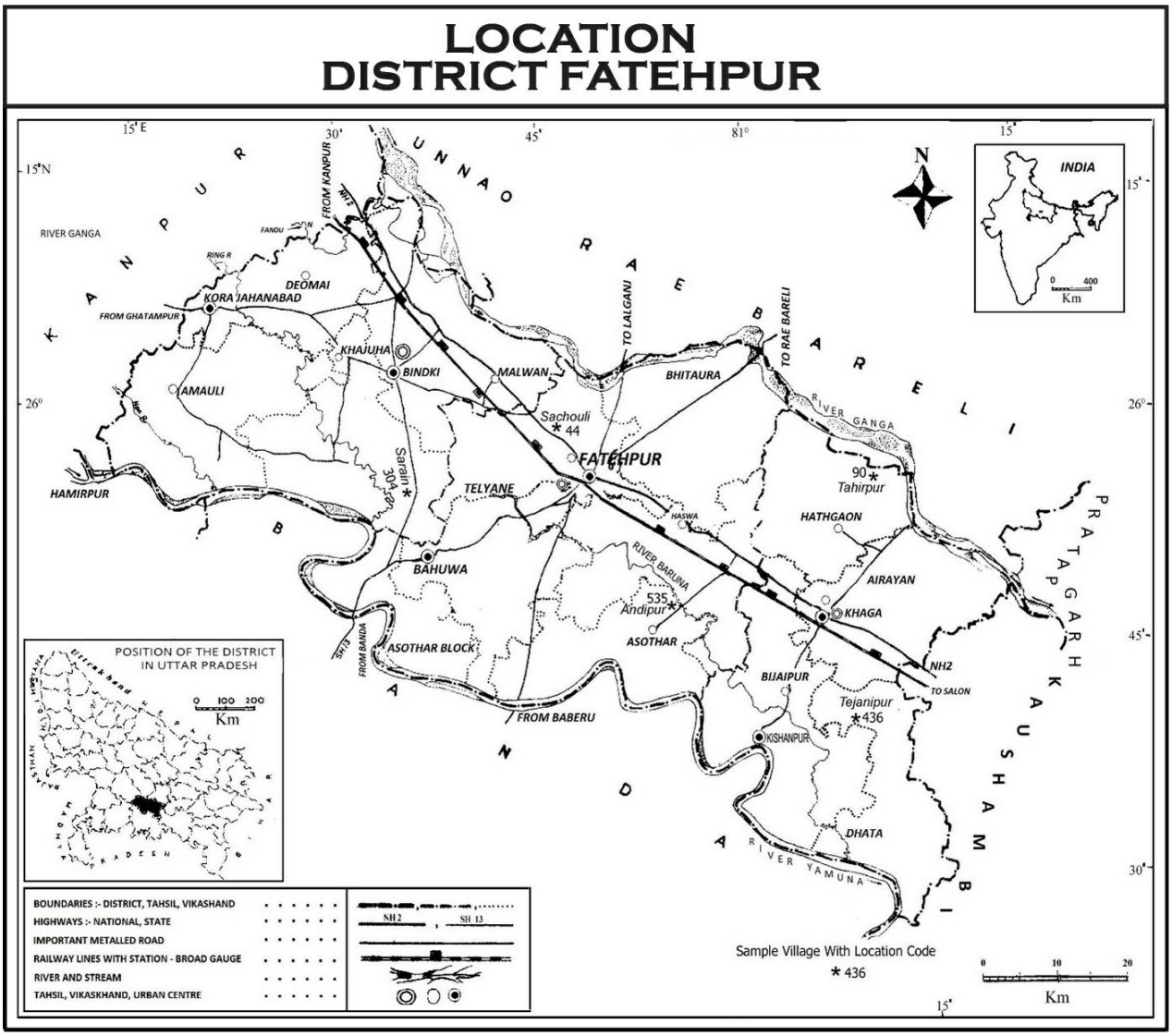

मानचित्र –1

गंगा की एक मात्र सहायक नदी पाण्डु नदी है जिसका प्रवाह उत्तर पूर्व को है जबकि यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ रिन्द, ससुर खदेरी छोटी व ससुर खदेरी बड़ी आदि है तथा बकरहा नाला, सूखा नाला, पनिहा नाला, छिलौली नाला, सूपा नाला, सहुंरा नाला, करारी नाला आदि छोटी–छोटी अवनलिकाएं है, जिनका प्रवाह ढ़ाल दक्षिण–पूर्व की ओर है जो यमुना नदी में मिल जाती हैं। यहाँ बलुई–दोमट एवं चिकनी मिट्टी विस्तृत भाग में पायी जाती है। जलवायु की दृष्टि से यह क्षेत्र मानसूनी विशेषता वाला है। अध्ययन क्षेत्र में सामान्यतः जीविकोनिर्वाहन कृषि की जाती है। अध्ययन क्षेत्र के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का लगभग 74 प्रतिशत भाग कृषि के अन्तर्गत समाहित है जिस पर विविध फसलों यथा धान, गेंहूँ चना, मसूर, मटर, एवं अन्य मोटे अनाज जैसी फसलों की विशेषीकृत एवं विविधीकृत दोनों ही प्रकार की कृषि स्थानीय भौगोलिक दशाओं के अनुसार की जाती है, साथ ही साथ कृषि अनुषंगीय व्यवसायों में पशु पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि भी कहीं–कहीं व्यावसायिक स्तर पर सम्पादित किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र ग्रामीण वातावरण से आबद्ध है जहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मावलम्बी लोग सौहार्दपूर्वक निवास करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण अवस्थापनात्मक तत्वों की

बहुतायत कमी है जो है भी उसकी दशा एवं दिशा दोनों ही खराब है। अतः ग्रामीण विकास हेतु कृषि तथा कृषि अनुषंगीय व्यवसायों के विकास के साथ ही साथ ग्रामीण अवस्थापनात्मक तत्वों के विकास पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास की अवधारणा

ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करने से है। लेकिन वर्तमान भारत में ग्रामीण विकास एक मूलभूत एवं जटिल समस्या के साथ प्रमुख उद्देश्य एवं नियोजनात्मक प्रक्रिया भी है, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या के जीवन को प्रमुखता प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रियान्तर्गत ग्रामीण पर्यावरण, ग्रामीण जनसंकुल विशेषतः गरीब एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों को लक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भूगोलविदों, समाज वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, नीतिनियोजकों, प्रशासकों और राजनीतिज्ञों द्वारा ग्रामीण समाज की संरचना, सामाजार्थिक साधनों का भू–वैन्यासिक विस्तार, नेतृत्व स्वरुप तथा जनसहभागिता के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए ग्रामीण समाज के सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं सीमित साधनों के मद्देनजर सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास की कल्पना समुचित ग्रामीण विकास के अभाव में साकार नही हो सकती। भारत गाँवों का देश है यदि गाँव सम्पन्न होंगे तो देश सम्पन्न होगा, यदि गाँव विपन्न होंगें तो देश विपन्न होगा। ग्रामीण विकास के महत्व को स्पष्ट करते हुए *महात्मा गांधी* ने कहा था कि 'प्रत्येक ऑख से ऑसू पोछना हमारा ध्येय होना चाहिए।' यही मूल कारण है कि हमारी विकास नीतियों, योजनाओं और राष्ट्रीय उन्नयन के विविध कार्यक्रमों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्व सर्वोपरि रहा है। सम्प्रति आज राष्ट्र के विकास एवं उत्थान में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एवं उत्थान, मूल मन्त्र सिद्ध हो रहा है।

ग्रामीण विकास की अवधारणा को समझने के लिए प्रथमतः 'ग्रामीण' और 'विकास' दोनों शब्दों को समझना आवश्यक है। पारिभाषिक दृष्टिकोण से 'ग्रामीण' शब्द का अभिप्राय उस क्षेत्र विशेष से है जो गैर शहरी पद्धति के जीवन, व्यावसायिक ढ़ाँचा, सामाजिक संगठन और व्यवस्था से संबद्ध होता है। इस प्रकार ग्रामीण शब्द उन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित है, जिनका जीवन यापन कृषि पर आधारित होता है और जो अत्यधिक रुप से प्रकृति पर निर्भर होता है, जिसकी व्यवस्थापन पद्धति में गाँवों या गृह स्थानों का समावेश होता है। सामाजिक रुप से यह अन्तःनिर्भरता का संकेत देता है एवं उसमें पूर्णतः सामुदायिक जीवन तथा प्रकृति व प्राकृतिक परिदृश्य के आस–पास निर्मित जीवन का धीमी गति से चलता हुआ सामंजस्य झलकता है (*मिश्रा एवं सुन्दरम्* 1979)।

'विकास' को परिभाषित करना एक दुरुह कार्य है, क्योंकि यह व्यक्ति व स्थान के सापेक्ष में अलग–अलग स्वरुपों में प्रयुक्त होता है। 'विकास' व्यक्तियों के उन्नति अथवा सुधार का गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन है (*वर्मा,* 1983)। विकास को एक परम्परागत एवं अभाव ग्रस्त उत्पादन से आधुनिक अर्थतन्त्र तक की मात्रात्मक उछाल प्रक्रिया के रुप में माना गया है, जिसके अन्तर्गत रोजगार के अवसर, उच्च आय एवं भावी प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु संसाधनों, पूंजी निवेश, एवं जनसंख्या का परम्परागत आर्थिक प्रखण्डों से तथाकथित

आधुनिक प्रखण्डों में स्थानान्तरण को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार घोर आर्थिक विपन्नता, बेरोजगारी एवं आय विषमता में क्रमिक ह्रास विकास है। *पामर* (1977) का कथन है कि "विकास एक ऐसी अन्तरानुशासिक प्रक्रिया है, जिसमें मानव पर्यावरण संगठित एवं पुनर्संगठित होता हैं।" इस रुप में विकास निवास्य तन्त्र का समग्र परिवर्तन है। विकास को ऐसी प्रक्रिया के रुप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा गरीबी, आर्थिक असमानताओं तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निवारण हो सके।

ज्ञातव्य है कि मात्र आय अथवा जीवन स्तर में मात्रात्मक वृद्धि ही विकास नही है। सही अर्थ में विकास तब होगा जब ऐसी संस्थागत एवं संरचनात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाये, जिससे दीर्घकाल तक उच्चतर जीवन स्तर एवं प्रगति के सुअवसर सुलभ हो सकें। इस प्रकार आय का न्याय संगत सामाजिक तथा भू–वैन्यासिक वितरण प्रतिरुप, उत्पादक रोजगार के अवसरों की उपलब्धि, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की सुलभता में अभिवृद्धि के साथ ही विकास प्रक्रिया में निर्भरता एवं सभी वर्गों की साझेदारी के लिए आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन और पारिस्थैतिकीय संरक्षण ही विकास है।

अतः विकास प्रक्रिया को जब ग्रामीण पर्यावरण एवं समाज के साथ अर्न्तसम्बन्धित किया जाता है, तो ग्रामीण विकास कहलाता है। ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उन धनात्मक परिवर्तनों से है, जो ग्रामीण समाज की आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। अतः ग्रामीण विकास एक क्षेत्रीय अवधारणा है, जिसमें मुख्य रुप से चार प्रकार के क्षेत्रों यथा सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं राष्ट्रीय आय में आवश्यकतानुसार धनात्मक परिवर्तन होने से है। दूसरे शब्दों में ग्रामीण विकास मानवीय कल्याण हेतु सामाजार्थिक रुप में संरचनात्मक परिवर्तन है, जो मुख्य रुप से कृषि, तकनीकी एवं जनसंख्या से सम्बन्धित है, (*मिश्रा एवं सुन्दरम्,* 1979)। अवधारणात्मक रुप में ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्णरुपेण विकास है। व्यापक सन्दर्भ में ग्रामीण विकास की संकल्पना भू–विन्यासगत ग्रामीण तन्त्र में सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित है। इस प्रकार कृषि उत्पादकता में वृद्धि, जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति आदि से सम्बन्धित सेवाओं और संस्थागत सुविधाओं का प्रावधान, स्थानीय सहयोग और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन, विभिन्न सामाजिक वर्गों को विकास के समान अवसर उपलब्ध करना ही ग्रामीण विकास का मुख्य लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में विपन्न समुदाय तक विकास की किरण पहुँचाना ग्रामीण विकास का उद्देश्य है (*देसाई एवं चौधरी,* 1977), जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यूनतम आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना है (*लेले,* 1978)।

ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्रामीण जनमानस का जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए तथा जीवन शैली में गुणात्मक परिवर्तन होने चाहिए। कृषि तथा लघु कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए, जिससे सामाजिक–आर्थिक अधिसंरचना में परिवर्तन हो सके। सारांशतः ग्रामीण विकास प्रक्रिया का मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों, विभिन्न सेवाओं व सुविधाओं का विस्तार एवं उनमें गुणात्मक परिवर्तन तथा उत्पादक क्रियाकलापों में वृद्धि द्वारा ग्रामीण परिवेश को श्रेयस्कर बनाना है। ग्रामीण निवास्य प्रत्यावर्तन में अर्थतन्त्र के विभिन्न प्रखण्डों में समन्वयन के अतिरिक्त सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पारिस्थैतिकीय एवं पर्यावरणीय समस्याओं का निराकरण भी

सम्मिलित है (*सिंह,* 1980)। ग्रामीण विकास स्वभाव में बहुअनुशासिक एवं क्रियान्वयन में बहुप्रखण्डीय है। इसमें कृषि विकास के अतिरिक्त उद्योग धन्धों की स्थापना, सामाजिक सुविधाओं यथा सड़क, संचार, विद्युत, विपणन, जलापूर्ति, बैंक, जनकल्याण सेवाएं व बीमारी नियन्त्रण, पोषण में सुधार, प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता जैसे कार्यक्रम सम्मिलित है। ग्रामीण विकास का सम्बन्ध आर्थिक प्रगति से ही नही, बल्कि ग्रामीण निर्धनों के सामाजिक कल्याण और प्रगति से भी है, जिसके अन्तर्गत विपन्न जनसंख्या के सक्रिय सहयोग पर आधारित आत्मनिर्भरता जैसे उद्देश्य सम्मिलित है। ग्रामीण विकास प्रत्यावर्तन बहुरुपीय यथा घटना, उपाय एवं श्रृंखला रुपीय होता है। घटना रुपीय ग्रामीण विकास भौतिक तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थात्मक कारकों के परस्पर प्रभावों का परिणाम है। वहीं उपाय रुपीय ग्रामीण विकास विशेषतः गरीबी समूहों की आर्थिक एवं सामाजिक अच्छाइयों से सम्बन्धित है। जबकि श्रृंखला रुप में ग्रामीण विकास की प्रकृति बहुयामी है जो कृषि विकास, सामाजिक, व्यावहारिक, अभियान्त्रिकीय एवं प्रबन्ध विज्ञानों से जुड़ा है (*सिंह,* 1986)। ग्रामीण विकास में *महात्मा गांधी* ने गाँवों के सर्वांगीण विकास के विचार को समाहित किया था, जिसमें मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष यथा सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक कारकों का पुनर्निर्माण, आत्मनिर्भर व स्वशाषित ग्रामों पर आधारित समाज का सृजन सम्मिलित है। *द्विवेदी* (1993) ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास का उद्देश्य लघु, स्वतन्त्र एवं स्वावलम्बी समुदायों का निर्माण करना है, जो ऐसे ग्रामों में निवास करते हों जहाँ जीवन सादा व शुद्ध हो तथा सभी परस्पर सहयोग व कठिन अध्यावसाय के फलस्वरुप सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतन्त्रता का उपयोग करते हों।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है होता कि ग्रामीण विकास एक व्यापक एवं बहुआयामी अवधारणा है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न पहलुओं यथा बहुक्षेत्रीय, बहुस्तरीय, बहुअभिकरणीय तथा बहुसमूह इत्यादि का विकास समाहित है। बहुक्षेत्रीय विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र (कृषि, औद्योगिक तथा अन्य), बहुस्तरीय विकास में ग्रामीण समाज के विभिन्न स्तरीय विकास में ग्रामीण समाज के विभिन्न स्तरों, बहुअभिकरणीय पहलुओं के अन्तर्गत सरकारी संस्थाएं व ऐच्छिक संगठन तथा बहुसमूह विकास के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों, जातियों एवं जनजातियों का विकास अन्तर्निहित है। फलस्वरुप ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कृषि विकास तो प्रथम स्थान रखता ही है, लेकिन समवेत ग्रामीण विकास का उद्देश्य ग्रामीण अर्थतन्त्र में बहुमुखी विकास से है यथा पूर्ण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य रहन–सहन के स्तर में गुणात्मक सुधार तथा स्थानीय जनता व ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं के संचालकों के नैतिक उत्थान से है, क्योंकि ग्रामीण विकास एक ऐसी ही संगठित कार्य पद्धति को व्यक्त करता है। ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय विकास की व्यवस्था को ग्रामीण अंचलों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों तक पहुँचाने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति एवं समान भू–वैन्यासिक वितरण अति महत्वपूर्ण है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास प्रक्रिया विविध प्रकार के समन्वयन पर आधारित है जिसका परम् उद्देश्य ग्रामीण अंचल में निवास करने वाली जनसंख्या को

रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना तथा दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में उसे अभीष्टतम् जीवन स्तर हेतु विविध सेवाएं एवं सुविधाएं सुलभ कराना है।

ग्रामीण विकास स्तर

ग्रामीण विकास में कृषि एवं कृषि अनुषंगीय व्यवसायों की भूमिका सर्वविदित है। भारत में धरातलीय विविधता के साथ–साथ अन्य भौगोलिक विविधताएं आज भी व्याप्त है, क्योंकि जहाँ धरातल पर वर्षा अधिक विचलनशील हो, सिंचाई के पर्याप्त स्रोत उपलब्ध न हो, वहाँ कृषक एक से अधिक फसलों को अपनाने एवं अन्य कृषि अनुषंगीय व्यवसायों को अपनाने में विश्वास करते है। शस्योत्पादन एवं कृषि अनुषंगीय व्यवसाय भी मूलतः ग्रामीण विकास के स्तर पर निर्भर करता है। जहाँ एक तरफ अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व जीविकोपार्जित कृषक कृषि विविधता में विश्वास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उच्च विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले धनी कृषक कृषि विशिष्टीकरण की तरफ अग्रसर होते हैं, जिससे किसी भी क्षेत्र के ग्रामीण विकास स्तरों में असमानता का पाया जाना स्वाभाविक ही है। इन्हीं असमानताओं को दृष्टिगत रखते हुए शोधकर्ता ने अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण विकास स्तर पर कृषिगत विविधता, सामाजार्थिक विकास एवं विकास सम्भाव्यता के स्तरों को मापनें का प्रयास किया है। ताकि अध्ययन क्षेत्र के लिए एक समन्वित एवं संधृत क्षेत्रीय विकास नियोजन प्रारुप निर्मित किया जा सके।

विकास स्तरों की संकल्पना एवं मापन विधियाँ

किसी प्रदेश के विकास स्तर का मापन भूगोलविदों, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों एवं नियोजकों का प्रमुख विषय रहा है, क्योंकि सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास हेतु निर्मित की जाने वाली योजनाओं के लिए विकास स्तर में क्षेत्रीय विभिन्नता का ज्ञान अपरिहार्य होता है। विकास स्तरों का मापन विभिन्न संकेतकों यथा राष्ट्रीय आय, प्रादेशिक उत्पादन, कुल घरेलु उत्पादन आदि द्वारा करने का विधान है। लेकिन कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रत्येक क्षेत्र या प्रदेश की आय वृद्धि को व्यक्त नही कर सकती, बल्कि कुल राष्ट्रीय आय वृद्धि के साथ ही साथ कभी–कभी प्रदेश स्तर पर ह्रास की प्रवृत्ति भी हो सकती है। इसीलिए विकास स्तरों का मापन उद्देश्यपरक क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुरुप परिवर्तनशील होते हैं। प्रारम्भिक समयों में विकास मापन हेतु अनुभाविक विधियों का प्रयोग किया जाता था लेकिन किसी भी क्षेत्र के विकास स्तरों का मापन सही एवं शुद्ध रुप से नही हो पाता था। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों ने मात्रात्मक विधियों का विकास किया। मात्रात्मक विधि के विकास का प्रथम प्रयास प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक *होटेलिंग* (1933) द्वारा प्रतिपादित एवं तदुपरान्त *हगूद* (1943), *बेरी* (1960), *मूसर व स्काट* (1961) एवं *सोजा* (1968) द्वारा अभिग्रहीत प्रधान संघटक विश्लेषण (Principal Component Analysis) था, जो एक संयुक्त सूचकांक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। *बर्नेट* (1951) ने विकास का एक अवित्तीय सूचकांक (Non Monetary Index) प्रस्तुत किया, जो अन्तर्राष्ट्रीय विभिन्नताओं को प्रतिबिम्बित कर सके। भारतीय विद्वानों में *दासगुप्ता* (1971) तथा *मित्रा* (1961 व 1967) ने विविक्तर विश्लेषण (Discriminant Analysis) को क्रम व्यवस्था के आधार पर विकास स्तरों का वर्गीकरण

करने के लिए प्रयोग किया। *पाठक, अजीज एवं चट्टोपाध्याय* (1970) ने ''समतुल्य सहसम्बन्ध विधि'' (Equal Correlation Method) का विकास बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल के विकास के लिए नियोजन क्षेत्रों के निरुपण हेतु किया गया है। *राव* (1973) *बनर्जी व पाण्डेय* (1985), *मोहम्मद* (1986), *चन्देल* (1991) आदि ने विभिन्न राज्यों व क्षेत्रों के आर्थिक विकास के मापन में ''बहुचरीय कारक विश्लेषण (Multivariate Factor Analysis) को प्रयुक्त किया। जबकि पोलैण्ड के गणितज्ञों एवं यूनेस्को (UNESCO) की संस्तुति का अनुसरण करते हुए *सिंह* (1984) नें "वर्गीकरण विधि" (Taxonomic Method) का सुझाव दिया, तदुपरान्त *श्रीवास्तव* (1982), *सिंह* (1984), *रावत* (1985), *सिंह एवं अन्य* (1988), *श्रीवास्तव, पी0 के0* (1990), *चन्देल एवं दीक्षित* (2004) आदि ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास स्तर की श्रेणी सूचकांक प्राप्त करने हेतु किया। शोधकर्ता ने फतेहपुर जनपद के ग्रामीण विकास स्तर के मापन हेतु "वर्गीकरण विधि" (Taxonomic Method) को अपनाकर ग्रामीण विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख चरों को आधार मानकर विकासखण्ड स्तर पर संयुक्त मान द्वारा ग्रामीण विकास स्तर का मापन एवं विश्लेषण किया है।

ग्रामीण विकास प्रतिरुपविकास सूचकांक, विकास प्रतिरुप व अनुरुपी आदर्श प्रदेश से क्रान्तिक दूरी का फलन है। यह मान 0.00 से 1.00 के मध्य आता है, यदि मान 0.00 के करीब होता तो अधिकतम विकास इंगित करता, और यदि 1.00 के करीब होता है, तो अल्पतम विकास का सूचक होता है।

ग्रामीण विकास के सूचकांक

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण विकास के सम्यक विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास स्तर के मापन एवं क्षेत्रीय वितरण प्रारुप हेतु ग्रामीण विकास के विविध पक्षों यथा सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना आदि से सम्बन्धित बीस सूचकांकों को लिया गया है जो निम्न है :

- कृषिगत भूमि का सकल क्षेत्रफल से प्रतिशत।
- सिंचित क्षेत्रफल का कृषित क्षेत्रफल से प्रतिशत।
- दो फसली क्षेत्रफल का कृषित क्षेत्रफल से प्रतिशत।
- सकल क्षेत्रफल से उच्च उत्पादकता वाले बीजों से आच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत।
- रासायनिक उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपयोग।
- व्यापारिक फसलों का सकल बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत।
- जनसंख्या घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर।
- प्राथमिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत।
- गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत।
- साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत।
- विद्युतकृत ग्रामों की संख्या।

- बायोगैस संयन्त्रों की संख्या।
- प्रति 10,000 जनसंख्या पर प्राइमरी विद्यालयों की संख्या।
- प्रति 10,000 जनसंख्या पर इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या।
- प्रति 10,000 जनसंख्या पर चिकित्सालयों की संख्या।
- प्रति 10,000 जनसंख्या पर चिकित्सीय शैय्याओं की संख्या।
- प्रति 10,000 जनसंख्या पर पशु चिकित्सालयों की संख्या।
- प्रति 10,000 जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई।
- प्रति 100 हेक्टेयर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर नलकूपों की संख्या।
- प्रति 100 हेक्टेयर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर सहकारी समितियाँ एवं वित्तीय संस्थाओं की संख्या।

ग्रामीण विकास स्तर का क्षेत्रीय प्रारुप

अध्ययन क्षेत्र के 13 विकासखण्डों में ग्रामीण विकास स्तर के मापन हेतु 20 सामाजार्थिक सूचकांकों के माध्यम से दो मानक वर्षों यथा 1990–91 एवं 2015– 16 का वर्गीकरण विधि द्वारा मापन कर संयुक्त मान प्राप्त किया गया। ज्ञातव्य हो कि जिस विकासखण्ड का संयुक्त मान जितना न्यून है वहाँ विकास का स्तर उतना ही उच्च है, इसके विपरीत सबसे अधिक संयुक्त मान वाले विकासखण्डों में विकास स्तर न्यूनतम है। संयुक्त मान की संख्या को अनुक्रमता के आधार पर तीन वर्गों यथा उच्च, मध्यम एवं निम्न में विभक्त कर अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण विकास स्तर का विश्लेषण किया गया (सारणी एवं मानचित्र – 2) है।

सारणी : ग्रामीण विकास स्तर का परिवर्तित प्रारुप

ग्रामीण विकास का स्तर	विकास सूचकांक	वर्ष			
		1990–91		2015–16	
		विकासखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (प्रतिशत)	विकासखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
उच्च	0.700 से कम	2	15.38	8	61.54
मध्यम	0.700 से 0.900	8	61.54	5	38.46
निम्न	0.900 से अधिक	3	23.08	–	–

उच्च ग्रामीण विकास स्तर के क्षेत्र

उच्च ग्रामीण विकास के अन्तर्गत वे विकासखण्ड आते हैं जहाँ सघन सिंचाई व्यवस्था के कारण उच्च उत्पादकता वाले बीजों एवं उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन उच्च पाया जाता है, साथ ही साथ इन विकासखण्डों में आधारभूत ग्रामीण सुविधाओं का विकास एवं अंगीकरण भी उच्च पाया जाता है। इस क्षेत्र के

ग्रामीण विकास का संयुक्त मान सूचकांक 0.70 से कम है। सारणी एवं मानचित्र (2) के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जहाँ वर्ष 1990–91 में उच्च ग्रामीण विकास के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों की संख्या मात्र दो यथा हसवा (0.51) एवं विजयीपुर (0.68) थी, जिनकी अवस्थिति अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण–पूर्व में पायी जाती है। जबकि वर्ष 2015–16 में तीव्र ग्रामीण विकास प्रक्रिया के कारण मध्यम व निम्न ग्रामीण विकास के अन्तर्गत आने वाले कुछ विकासखण्ड प्रोन्नति कर उच्च ग्रामीण विकास वर्ग में सम्मिलित हो जाने से इस वर्ग में विकासखण्डों की संख्या बढ़कर आठ हो गयी। जिनका मुख्य संकेन्द्रण अध्ययन क्षेत्र के पश्चिम में अवस्थित विकासखण्ड तेलियानी (0.52), अमौली (0.73), खजुहा (0.68), देवमई (0.66), एवं मलवां (0.64) तथा पूर्व में अवस्थित विकासखण्ड हसवा (0.65), धाता (0.64), ऐराय (0.64), एवं हथगांम (0.53) के रुप में पायी जाती है। सामान्यतया इन विकासखण्डों में उच्च कृषिगत भूमि के साथ–साथ व्यवस्थागत कारकों का विकास एवं अंगीकरण उच्च पाया जाता है।

मध्यम ग्रामीण विकास स्तर के क्षेत्र

मध्यम ग्रामीण विकास के अन्तर्गत वे विकासखण्ड आते हैं जहाँ सकल बोया गया क्षेत्रफल, उच्च उपादकता वाले बीज एवं उर्वरकों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर औसत होने के कारण उत्पादन भी औसत ही पाया जाता है, साथ ही साथ इन विकासखण्डों में आधारभूत ग्रामीण सुविधाओं का विकास एवं अंगीकरण भी औसत पाया जाता है। इस क्षेत्र का ग्रामीण विकास का संयुक्त मान सूचकांक 0.70 से 0.90 के मध्य पाया जाता है। क्षेत्रीय एवं कालिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जहाँ वर्ष 1990–91 में मध्यम ग्रामीण विकास के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों की संख्या आठ थी, जिनका मुख्य संकेन्द्रण अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमोत्तर में पायी जाती थी। वहीं 2015–16 में तीव्र ग्रामीण विकास प्रक्रिया के कारण जो विकासखण्ड 1990–91 में निम्न ग्रामीण विकास वाले वर्ग में सम्मिलित थे, वे प्रोन्नत होकर या तो उच्च विकास स्तर वाले क्षेत्रों में या तो मध्यम ग्रामीण विकास स्तर में सम्मिलित होने से विकासखण्डों की संख्या घटकर पाँच रह गयी, जिनका मुख्य संकेन्द्रण अध्ययन क्षेत्र के दक्षिण में पायी जाती है। जिसमें विकासखण्ड असोथर (0.82), बहुवा (0.82), एवं विजयीपुर (0. 82) सम्मिलित है। जबकि गौण संकेन्द्रण पश्चिम में स्थित विकासखण्ड अमौली (0.73) तथा उत्तर में स्थित विकासखण्ड भिटौरा (0.90) में पायी जाती है। सामान्यतः निम्न ग्रामीण विकास स्तर वाले वे विकासखण्ड है जिनका संयुक्त मान सूचकांक 0.90 से अधिक है। इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों की अवस्थिति वहाँ पायी जाती है जहाँ ग्रामीण विकास प्रक्रिया को संचालित करने वाले चर निम्न स्तरीय है विशेषकर बीहड़ीकृत क्षेत्र। यदि इसके क्षेत्रीय वितरण प्रारुप के परिवर्तित स्वरुप पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि जहाँ वर्ष 1990–91 में इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों की संख्या तीन यथा असोथर (0.98), धाता (0.92) तथा हथगांम (0.91) थी, वहीं तीव्र ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं विशेषतः सिंचाई साधनों में बढ़ोत्तरी व सघनता तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सघन संचालन एवं अंगीकरण के कारण वर्ष 2015–16 में इस वर्ग के अन्तर्गत विकासखण्डों की संख्या नगण्य हो गयी, क्योंकि इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्ड प्रोन्नत कर उच्चतर ग्रामीण विकास स्तर वाले क्षेत्रों में सम्मिलित हो गये।

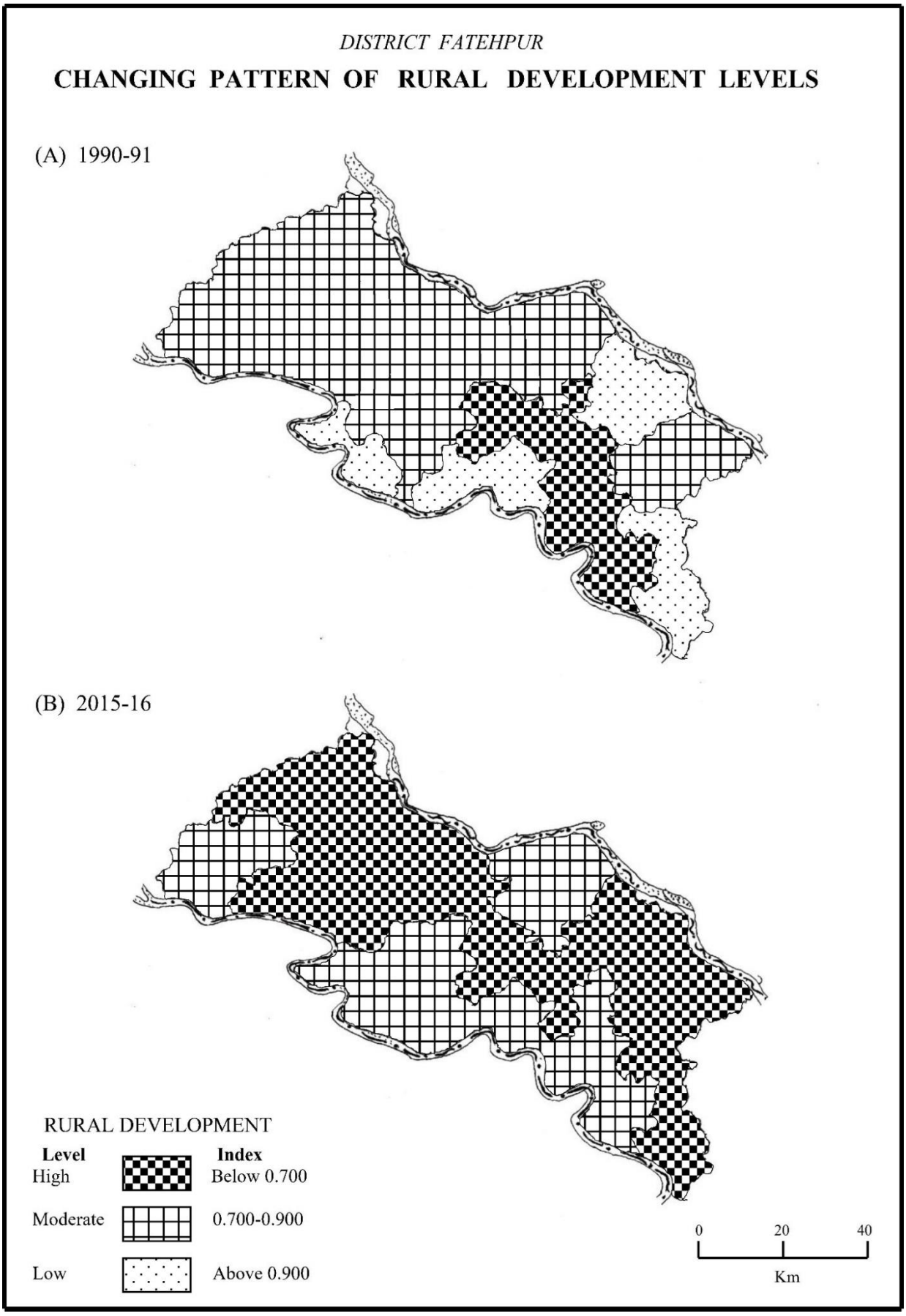
DISTRICT FATEHPUR
CHANGING PATTERN OF RURAL DEVELOPMENT LEVELS
(A) 1990-91
(B) 2015-16
RURAL DEVELOPMENT
Level
Index
High
Below 0.700
Moderate
0.700-0.900
Low
Above 0.900
0
20
40
Km

मानचित्र –2

निम्न ग्रामीण विकास स्तर के क्षेत्र

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में आठ विकासखण्ड ऐसे है जहाँ उच्च ग्रामीण विकास पाया जाता है और इनकी अवस्थिति सामान्यतः समतल मैदानी क्षेत्रों के उच्च उर्वरता वाले मिट्टी कटिबन्ध में पायी जाती है। जहाँ समुचित सिंचाई यातायात व्यवस्था के साथ–साथ सामाजार्थिक अवस्थापना तत्वों का पर्याप्त विकास व अंगीकरण पाया जाता है। विकासखण्ड विजयीपुर में कृषित भूमि तथा उच्च उत्पादकता वाले बीजों के प्रयोग में घटोत्तरी हो जाने के कारण ग्रामीण विकास स्तर 1990–91 की तुलना में 2015–16 में गिरा है। मात्र 5 विकासखण्ड ऐसे है, जहाँ विकास की प्रतिबन्धित परिस्थितियाँ (नदी तटीय बीहड़ीकृत क्षेत्र) पायी जाती है। वहाँ ग्रामीण विकास मध्यम स्तर का पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास निरन्तर प्रगति पर है।

ग्रामीण विकास की समस्याएं एवं संधृत नियोजन

ग्रामीण विकास वर्तमान भारत की मूलभूत एवं जटिल समस्या के साथ–साथ प्रमुख उद्देश्य एवं नियोजनात्मक प्रक्रिया है। जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण जनता के जीवन को प्रमुखता प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्रामीण पर्यावरण कृषि विकास, जनसंकुल ग्रामीण क्षेत्रों विशेषतः गरीब एवं समाज के अन्य लोगों के लिए लक्षित किया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ग्रामीण समस्याएं सिर्फ असमानताओं, गरीबी तथा संसाधनों के समुचित उपयोग वितरण से नही है, वरन् शस्य विविधता में कमी; स्थिर या घटती कृषि उत्पादकता, कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल, वन, खनिज आदि की कमी, मृदा उर्वरता में गिरावट, मानव संसाधन की गुणवत्ता में कमी, स्वास्थ सेवाओं एवं सुविधाओं का अभाव, कृषि पर आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, परिवहन एवं संचार, ग्रामीण विकास के अन्य अवस्थापनात्मक तत्वों और निवेश में कमी तथा रोजगार के अवसरों में कमी भी कई समस्याओं की मूल जड़ में है। साथ ही साथ तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा भूमि तक सीमित पहुँच भी ग्रामीण विकास में बाधक है।

ग्रामीण विकास स्तर के मापन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण विकास अपेक्षित स्तर का नही है बल्कि असन्तुलित है परन्तु ग्रामीण विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं निहित है। इसलिए यह आवश्यक है कि संधृत ग्रामीण विकास के प्रमुख घटकों विशेषतः कृषि विविधता हेतु कृषि भूमि के बेहतर उपयोग के लिए बाजार मांग तथा कृषि पारिस्थितिकीय को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैः

- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं का विकास।
- स्थानीय परिस्थितियों के अनुरुप स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास।
- गुणवत्ता युक्त परिवहन एवं संचार सुविधाओं का विस्तार एवं विकास।
- सघन एवं कुशलतम प्रशासनिक सुविधाओं का विकास।
- ग्रामीण विकासपरक वित्तीय संस्थाओं का विकास।

- कृषि उत्पाद आधारित केन्द्रों का विकास।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी सेवाओं का विकास।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एवं कुक्कुट पालन विकास को प्रोत्साहन।
- स्थानीय कृषि उत्पाद एवं मांग के अनुरुप औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु सस्ता ऋण एवं प्रोत्साहन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त विद्युतीकरण एवं पेयजल सुविधाओं का विकास।
- ग्रामीण विकास हेतु शोध एवं शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा उन्हें ग्रामीणों एवं गैर सरकारी संगठनों (NGO) के सहयोग से ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण विकास से जुड़े लोगों एवं संस्थाओं की एक निर्देशिका तैयार करना तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने वाले कृषकों को व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ–साथ पुरस्कृत करना।
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तरों पर समन्वयन एवं सन्दर्भ केन्द्रों की स्थापना कर ग्रामीण विकास के बारे में ग्रामीण लोगों को अधिक जानकारी प्रदान करने के साथ ही ग्रामीण विकास में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना।
- ग्रामीण विकास आन्दोलन को ग्रामीण जीवन पद्धति के साथ आवश्यक रुप से अंगीकार करने हेतु अनेकानेक योजनाओं, कार्यक्रमों का संचालन।
- पारम्परिक एवं आधुनिक कार्यक्रमों का आंकलन एवं विश्लेषण के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।
- ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत सभी संस्थाओं को एक साथ आगे बढ़ने हेतु दीर्घ कालिक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन।
- ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण व संचालन करना चाहिए, जिसमें बिना सामाजिक एवं आर्थिक अन्तर के सभी लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ मिल सके।

सन्दर्भ सूची

[1]. चौहान, एस0 एस0 एवं सिंह, साधना (2004), ''ग्रामीण विकास पूरा मॉडल : ग्रामीण क्षेत्र में सुख–सुविधा मुहैया की योजना'', **कुरुक्षेत्र,** अंक 7 (जुलाई), पृष्ठ 6–10।

[2]. देव, प्रकाश (2005), "ग्रामीण आवास योजनायें : प्रगति की नई शुरुआत", **कुरुक्षेत्र,** अंक 12 (अक्टूबर), पृष्ठ 15।

[3]. दुबे, बेचन एवं सिंह, मंगला (1985),**"समन्वित ग्रामीण विकास"**, जीवन धारा प्रकाशन, वाराणसी, पृष्ठ 320।

[4]. कलवार, सुमनचन्द्र एवं मीणा, तेजराम (2001), **''ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास'',** पोइन्टर पब्लिसर, जयपुर।

[5]. शर्मा, रंजन (2000), "विलासपुर में कृषि एवं पोषण स्तर",**उत्तर भारत भूगोल पत्रिका,** गोरखपुर, अंक 36, संख्या 1व 2, पृष्ठ 51।

[6]. सिंह, अजीत कुमार एवं गोयल, सुजीत कुमार (2005), "मुरादाबाद जनपद में ग्रामीण विकास का स्तर", **भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका,** अंक–9, संख्या–1, पृष्ठ 1–7।

[7]. सिंह, एस. बी. (2003), ''झाँसी सम्भाग में कृषि विकास के स्तर का भू–वैन्यासिक प्रतिरुप एवं नियोजन", **उत्तर भारत भूगोल पत्रिका,** अंक 39, संख्या 1 एवं 2, पृष्ठ 37–43।

[8]. वर्मा, एस.एस. एवं शाही, एस. के. (1986), ''अवस्थापनात्मक तत्व एवं प्रादेशिक विकास फरेन्दा तहसील का प्रतीक अध्ययन'', **भू विज्ञान पत्रिका,** अंक 2, भाग–1, पृष्ठ 25–34.

[9]. Araki Hitoshi and Chandel,R.S.(2013)India Introduction of New Commercial Crop into a Rural Village : Case of Horticultue Production in Dedaur Village , U.P., India, **Geographical Review of Japan**, Series B ,The Association of Japanes Geographical Journal, Vol.86, No.2,pp.174-188.

[10]. Chandel, R.S. (1991), "Agricultural Change in Bundelkhand Region", **Star Distributors**, Varanasi, pp. 134-146.

[11]. Chandel, R.S. and Dixit, K. K. (2004), "Rural Transformation and Sustainable Planning", **Indian Research Journal of Social Science**, Vol. 8, No. 1, pp. 39-48.

[12]. Chandel, R.S. (2009), "Sustainable Planning of Energy Relation to Rural Development", **The Rohilkhand Geographical Journal of India**; (Hindi), Vol. 6, pp. 142-150.

[13]. Mishra, R. P. and Sundaram. K.V. (1979), "Rural Development Perspective and Approaches", **Sterling Publishers Pvt. Ltd.**, New Delhi.

[14]. Mishra, R.P. and Sundaram, K.V. (1980), "Multi Level Planning and Integrated Rural Development in India", **Heritage Publisher**, New Delhi.

[15]. Roy, Kumkum. (1995), "Spatial Pattern of Rural Development and Social Change: A Case Study of Phulpur Tahsil of Azamgarh District", **National Geographer**, Vol. XXX, No. 2, pp. 177-184.

[16]. Sharma, Poonam (1995), "Regional Inequalities in the Process of Socio-Economic Development", **Annals of N.A.G.I.**, Vol. XV, pp. 31-52.

[17]. Singh, M.B. and Chandel, R. S. (1990), "An Assessment of Agricultural Changes in Three Villages of Jalaun District, U.P.," **Geographica Iugoslavica (Yugoslavia)**, Vol. XII, pp. 77-85.

[18]. Singh, M.B. and Chandel, R. S. (1994), "Sustainability of Irrigation Base Agriculture in India", **Annals of N.A.G.I.**, Vol. XIV, No. 2, pp. 45-51.

[19]. Singh, M.B., Chandel, R.S. and Singh, R. (1994), "Sustainable Rural Systems in Developing Countries: An Indian Experience,"1994 **IGU Residential Conference Proceedings**, (on CD-ROM) Prague, Czech Republic.

[20]. Singh, M. B., and Chandel, R. S. (1998), "An Appraisal and Management of Wastelands: A Case Study", **N.G.J.I.**, Vol. 44, Pts. (1-4), pp. 173-180.

[21]. Singh, V.R. and Singh, N. K. (1986), "Perspectives Agricultural Typology", (ed), **Star Distributors (Publication Division)**, Varanasi.

[22]. Singh, V.R. and Chandel, R.S. (1991), "Level of Agricultural Development and Planning in Bundelkhand Region," Agriculture: Planning and Development, (ed) M. V. Reddy and others, **UBS Publishers and Distributors Ltd.**, Madras, pp. 83- 93.

[23]. Verma, R.V. (2005), "Identification of Viable Spatial Units for Sustainable Rural Development," Balheshwar Thakur and Others (eds) Urban and Regional Development in India, Vol.2, **Concept Publishing Company**, New Delhi, pp. 391-410.